POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2017/अंक 11

मासिक प्रेषण दि. 8 नवम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 नवम्बर, 2017 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! साथ ही 'ग्राम गदर' के सभी पाठकों को मेरी एवं 'कट्स' परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!

यह सुखद खबर है कि नीति आयोग भारत में कुपोषण से निपटने के लिए व्यापक पोषण रणनीति और उसके क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को तेजी से विकसित करने पर जोर दे रहा है।

पोषकता निर्धारण में स्वास्थ्य सेवाएं, खाद्य पदार्थों की शुद्धता, पीने का साफ पानी, साफ-सफाई के साथ-साथ लोगों की आजीविका में सुधार आदि महत्वपूर्ण माने गए हैं। पोषकता के लक्ष्य को पाने के लिए इन सेवाओं को गांव-गांव तक ले जाना होगा। अभी भी यह सभी सेवाएं गरीब की पहुंच से काफी दूर हैं। इन सेवाओं को खरीदने की उनकी क्षमता को बढ़ाना केवल 'गरीबी हटाओ' के नारे से संभव नहीं।

हालांकि कुपोषण की समस्या से निजात पाने के लिए देश में स्कूली बच्चों को मुफ्त पोषक आहार देने के लिए 'मिड डे मील' योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं को पोषणयुक्त खाद्य सामग्री का वितरण जैसी कई अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन सभी सरकारी तंत्र की कमजोरियों और सामाजिक निगरानी की कमी के चलते कुछ ही समय बाद भ्रष्टाचार के जाल में जा फंसती हैं। नीति आयोग को इस पहलू पर भी खास ध्यान देना होगा।

अच्छा हो यदि कुपोषण मुक्त भारत के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ समाज भी अपनी भागीदारी निभाने में आगे आए।

राजस्थान सूचना आयोग का महत्वपूर्ण फैसला

राज्य में अब मंत्रियों से भी मांग सकेंगे सूचना

राजस्थान सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार कानून लागू होने के 12 साल बाद भी मंत्री कार्यालय इसके दायरे में नहीं आने पर नाराजगी व हैरानी जताई है। आयोग ने साफ किया है कि मंत्रियों का कार्यालय भी इस कानून के दायरे में है। आयोग ने कानून के तहत स्वतः सार्वजनिक की जाने वाली करीब डेढ़ दर्जन तरह की सूचनाओं को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद अब मंत्रियों के कार्यालय से सीधे सूचना मांगी जा सकेगी। मुख्य सचिव को एक माह में लोक सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय अधिकारी नियुक्त कराने को कहा है। सूचना आयुक्त आशुतोष शर्मा ने गौरीशंकर मालू की अपील पर यह आदेश दिया। आयोग ने इस बात पर हैरानी जताई कि जब मुख्यमंत्री का कार्यालय सूचना के अधिकार कानून के दायरे में है, तो मंत्रियों के कार्यालयों के लिए ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है?

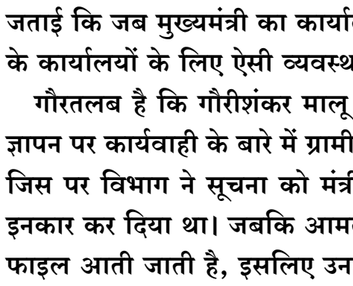

गौरतलब है कि गौरीशंकर मालू ने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री को दिए एक ज्ञापन पर कार्यवाही के बारे में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सूचना मांगी थी, जिस पर विभाग ने सूचना को मंत्री के कार्यालय से संबंधित बताते हुए उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। जबकि आमतौर पर यह माना जाता है कि मंत्री के पास विभाग से ही फाइल आती जाती है, इसलिए उनका पूरा रिकॉर्ड विभाग में उपलब्ध रहता है।

लोन चुकता होने पर भी दस्तावेज नहीं लौटाना बैंक को भारी पड़ा

जयपुर निवासी सुनील खंडेलवाल ने आईडीबीआई बैंक के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण मंच (द्वितीय) में परिवाद दर्ज कराया। अपने वकील के जरिए दर्ज कराए गए परिवाद में बताया गया कि उन्होंने वर्ष 2009 में आईडीबीआई बैंक से मकान के मूल दस्तावेज गिरवी रखकर होम लोन लिया था। उन्होंने बैंक से लिए गए होम लोन का ब्याज सहित पूरा भुगतान कर दिया। लेकिन लोन चुकता होने के बावजूद बैंक उन्हें मकान के मूल दस्तावेज नहीं लौटा रहा और दस्तावेज गुम होने की बात कह रहा है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने बैंक द्वारा मूल दस्तावेज नहीं लौटाने को सेवा दोष माना और कहा कि बैंक द्वारा उपभोक्ता को मूल दस्तावेज वापस नहीं लौटा कर मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। डुप्लीकेट कागजात मिलने पर भी उन्हें असल दस्तावेजों की कमी जीवन पर्यन्त खलती रहेगी। जेडीए से पट्टा जारी करवाते समय या भूखण्ड को बेचते समय समस्त कागजात देकर सामने वाले को सन्तुष्ट करना होगा। इससे हमेशा असुविधा बनी रहेगी।

मंच ने इस तथ्यों पर विचार करते हुए आईडीबीआई बैंक को आदेश दिए कि वह सुनील खंडेलवाल को 55,000 रुपए बतौर हर्जाना अदा करें। साथ ही उन्हें परिवाद व्यय के तौर पर अलग से 5,000 रुपए भी दिए जाएं।

राजस्थान जैविक कृषि की ओर अग्रसर-कृषि आयुक्त

खेती में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग से कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। मद्देनजर अब राजस्थान लगातार जैविक खेती की ओर बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण यहां की मिट्टी का परम्परागत रूप से जैविक खेती से जुड़ा होना है।

राजस्थान कृषि विभाग के आयुक्त विकास सीताराम भाले ने यह विचार 'कट्स' द्वारा 'ग्रीन एक्शन वीक' 2017 के तहत जयपुर में आयोजित 'सभी के लिए सतत सुरक्षित भोजन' पर परिचर्चा का उद्घाटन करते हुए व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि केन्द्र व राज्य सरकार अब जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार की पहल पर परम्परागत कृषि विकास योजना के रूप में 1150 कलस्टर विकसित किए गए है जिसमें 1 कलस्टर 50 हैक्टर का है। इसके साथ ही घरों में भी उपलब्ध संसाधनों के उपयोग से 'किचन गार्डन' के माध्यम से जैविक उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

कार्यक्रम में राज्य कृषि प्रबन्धन संस्थान के निदेशक डॉ. शीतल प्रसाद शर्मा ने रासायनिक खेती के नकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हुए कहा कि भारत में सभी किस्मों के बीज उपलब्ध हैं, इन्हें विकसित करने में कृषि अनुसंधान केन्द्रों को आगे आना होगा।

'कटस' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने अपने प्रारम्भिक सम्बोधन में विभिन्न आंकड़ों और तथ्यों को सामने रखते हुए भारत में जैविक खेती को तेज गति से बढ़ाने, जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण और सतत उपभोग की पैरवी की।'कट्स' की परियोजना सहायक निमिषा गौड़ ने एक माह के अभियान के दौरान की गई गतिविधियों और इसके परिणामों पर प्रस्तुतिकरण दिया।

कार्यक्रम का तकनीकी सत्र का संचालन 'कट्स' के सहायक निदेशक दीपक सक्सेना ने किया, जिसमें कई कृषि विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में 100 से भी अधिक किसानों, कृषि विशेषज्ञों, उपभोक्ता संस्थाओं मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

देश में है सुशासन की कमी-मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में संसाधनों की नहीं बल्कि सुशासन की कमी है। ग्रामीण विकास के लिए सुशासन का प्रयास जारी है। आने वाले दिनों में ग्रामीण विकास पर सरकार का ज्यादा जोर होगा।

उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में ज्यादा गरीबी है, वहां मनरेगा का काम कम हो रहा है। जिन राज्यों में सुशासन है, वहां मनरेगा का काम ज्यादा हो रहा है। उन्होंने कहां कि गांवों और शहरों को समान सुविधाएं मिलनी चाहिए। शहरों में ग्रामीण उत्पादों के विक्रय के लिए बाजार बनने चाहिए। इससे ग्रामीण प्रोद्योगिकी को बढ़ावा मिल सकेगा।

किसानों को दिए जाएंगे रुपे कार्ड

सहकारी बैंकिग के जरिए किसानों को लाभान्वित करने के लिए सहकारिता विभाग अब उनके घर जाकर रुपे कार्ड उपलब्ध कराएगा। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल एटीएम वैनों के माध्यम से यह कार्ड वितरित किए जाएंगे। यह काम दो माह में पूरा कर लिया जाएगा।

सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को योजनाओं का समय पर लाभ मिल सके इसके लिए गांव के अटल सेवा केंद्र, पंचायत भवन, ग्राम सेवा सहकारी समिति या क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के पास सहकारी बैंकिंग सेवा की सुविधा के लिए भी इन मोबाइल एटीएम वैनों को तैनात किया जाएगा।

हर घर में होगा पेयजल कनेक्शन

अब एक हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में भी घर-घर पानी का कनेक्शन होगा। सीमांत क्षेत्रों के गांवों के लिए तीन हजार की आबादी के नियम में शिथिलता देते हुए यह नीतिगत फैसला लिया गया है।

यह जानकारी जलदाय मंत्री सुरेन्द्र गोयल ने नीति निर्धारण समिति की बैठक में देते हुए बताया कि प्रदेश के कई शहरों और गांवों में पेयजल योजनाओं के वर्तमान स्वरूप से उन्नत तरीकों में बदलने और बड़ी परियोजनाओं से जोड़ने का नीतिगत फैसला लिया गया है।

प्रदेश में नदियों को जोड़ा जाएगा

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा है कि प्रदेश को जल संकट से बचाने के लिए 40 हजार करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में नदियों को जोड़ने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि जल संकट को लेकर राज्य सरकार पहले से ही संवेदनशील है। जल स्वावलंबन अभियान के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने से कई जिलों के डार्क जोन में पानी का संकट दूर हुआ है। नदियों को जोड़ने के लिए बनी योजना के तहत हाड़ौती की परवन, पार्वती और कालीसिंध को जोड़ा जाएगा। इससे राज्य के 13 जिले लाभान्वित होंगे।

जैविक खेती बचाएगी बीमारियों से

कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने कहा है कि जैविक खेती से ही हम धरती माता को जहर से बचा सकते हैं। जैविक खेती के उत्पाद बीमारियां रोकने में भी कारगर हैं।

जयपुर स्थित पिंजरापोल गोशाला में जैविक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि 1966 में भारत में जैविक खेती हुआ करती थी। इसके बाद खेती में रसायनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे जहरीले रसायन धरती में समाते गए। इसके दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। उन्होंने कहा कि जैविक खेती से धरती मां की सेहत अच्छी रहेगी तो हम सभी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा।

गोमूत्र और गोबर से होगी कमाई

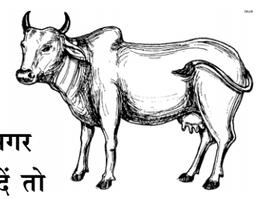

गांवों में गैर दुधारू खासकर गोवंश की अनदेखी होती है। किसान अगर ड्राई डेयरी पर ध्यान दें तो गैर दुधारू गोवंश से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। ड्राई डेयरी मॉडल गांव स्तर पर रोजगार सृजन में काफी मददगार साबित हो सकता है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री गिरिराज सिंह ने बताया है कि ड्राई डेयरी के माध्यम से किसानों को जैविक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। गौमूत्र व गोबर से तैयार किए गए एमिनो एसिड और जैविक खाद का उपयोग करके कृषि उत्पादन में 20 से 25 फीसदी तक बढ़ोतरी की जा सकती है।

कुपोषण की समस्या

देश में कुपोषण से गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं सामने आ रही हैं। कई गंभीर बीमारियों की वजह भोजन में पोषक तत्वों की कमी का होना है। भोजन में प्रोटीन, विटामिन और आयरन जैसे कई पोषक तत्वों की कमी से 46 फीसदी से भी ज्यादा लोग जूझ रहे हैं। इससे टीबी, कैंसर, अस्थमा, हृदय रोग और मधुमेह जैसी कई गंभीर बीमारियों में तेजी से इजाफा हो रहा है।

खेती में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का उपयोग, बढ़ता प्रदूषण और खाद्य पदार्थों में मिलावट इसकी खास वजह है। जरूरत यह है कि जन स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बन रही ऐसी समस्याओं को सरकार और समाज मिलकर हल करने में आगे आए। -कमलेश भारद्वाज, जयपुर

सौभाग्य योजना से होगा हर घर रोशन

केंद्र सरकार ने अगले सवा साल में देश के हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए 'सौभाग्य' योजना शुरू की है। इसके तहत करीब चार करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। इस योजना का लाभ राजस्थान के करीब 10 लाख परिवारों को भी मिलेगा।

सौभाग्य
प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना

अभी प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है। इस योजना से पहले प्रदेश में करीब 18 लाख परिवार बिजली की रोशनी से वंचित थे। अनुमान है इस योजना के बाद भी करीब10 लाख परिवार बिजली की रोशनी से वंचित रह जाएंगे। ऐसे परिवार भी सौभाग्य योजना के तहत मुफ्त बिजली कनेक्शन पा सकेंगे।

नसबंदी की सजा भुगत रही महिलाएं

नागौर निवासी रतनलाल की पत्नी प्रेम की पिछले साल नसबंदी के दौरान मौत हो गई। विभाग ने रतनलाल को एक लाख रुपए का मुआवजा देकर अपनी गलती पर पर्दा डाल दिया। अब रतनलाल मजदूरी करता है और घर आकर अपने तीन बच्चों को संभालता है। यह कोई एक मामला नहीं है, पिछले दो साल में प्रदेश में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान 12 महिलाओं की मौत हो गई।

इसके अलावा प्रदेश में हजारों महिलाएं हर साल नसबंदी फेल होने की भी सजा भुगत रही हैं। प्रदेश में हर साल 2000 से भी ज्यादा नसबंदी ऑपरेशन फेल हो रहे हैं। इतना ही नहीं राज्य सरकार को हर साल औसतन 8 से 10 करोड़ रुपए नसबंदी फेल होने की वजह से मुआवजा चुकाना पड़ रहा है।

मनरेगा योजना का हाल बेहाल

अजमेर के गांव जटिया पीतावास की पुष्पा देवी के मनरेगा के चार हजार से ज्यादा रुपए पिछले छह महीने से अटके हुए हैं। उन्हें काम के बाद मजदूरी नहीं मिल रही। यह दर्द सिर्फ पुष्पा का ही नहीं प्रदेश में देरी से भुगतान के मामले में मजदूरी के 140 करोड़ रुपए अटके हुए हैं।

इतना ही नहीं हर परिवार को साल में 100 दिन काम देने की इस योजना में इस साल अब तक सिर्फ 12535 परिवारों यानी 13 फीसदी लोगों को ही 100 दिन काम मिला है। जबकि इस साल सरकार योजना का 97 फीसदी पैसा खर्च कर चुकी है। इस साल के कामों में से 99 फीसदी से ज्यादा काम अधूरे पड़े हैं। गौरतलब यह है कि चौंकाने वाली इन खबरों पर सरकार ने भी मौन साध रखा है।

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485